

गुरुग्राम शहर में अंतिम छोर तक जलापूर्ति की 20 किमी नई मास्टर वाटर सप्लाई लाइन बिछेगी : मनोहर लाल

पायनियर समाचार सेवा | गुरुग्राम

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के माध्यम से गुरुग्राम शहर के विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूटी रेस्ट हाउस में शनिवार देर शाम गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के 12वें बैठक आयोजित हुई। सीएम मनोहर लाल ने प्राधिकरण के सदस्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करते हुए वर्ष 2023-24 के लिए 2574.40 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट की स्वीकृति प्रदान की।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूटी रेस्ट हाउस में शनिवार देर शाम गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के 12वें बैठक आयोजित हुई। सीएम मनोहर लाल ने प्राधिकरण के सदस्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करते हुए वर्ष 2023-24 के लिए 2574.40 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट की स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूटी रेस्ट हाउस में शनिवार देर शाम गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के 12वें बैठक आयोजित हुई। सीएम मनोहर लाल ने प्राधिकरण के सदस्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करते हुए वर्ष 2023-24 के लिए 2574.40 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट की स्वीकृति प्रदान की।

वार्षिक बजट में ढांचागत तंत्र (सङ्कर, जलापूर्ति, सीवरेज, स्टोर्म वाटर आदि) के लिए 570.06 करोड़ रुपए, कैपिटल वर्क के लिए 1151.77 करोड़ रुपए, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं विशेषकर शीतला माता मंदिर के लिए



गुरुग्राम में जीएमडीए की 12वें बैठक लेते मुख्यमंत्री मनोहर लाल।

300 करोड़ रुपए, शहरी पर्यावरण के लिए 36 करोड़ रुपए, अपेक्षण एंड मैनेस के लिए 538 करोड़ रुपए का प्रवाहन किया गया था। वार्षिक बजट के लिए प्राधिकरण के पास 2043.17 करोड़ रुपए का जलसव विभिन्न मंडों से प्राप्त होगा साथ ही शेष 531.23 करोड़ रुपए की आवश्यकता पहले से उत्पन्न वार्षिक फंड से पूरी की जाएगी।

टेल एंड सेक्टर तक पानी पहुंचाने के लिए 125 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत : गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की वैठक में शहर के विभिन्न क्षेत्रों तथा

भी नई मास्टर वाटर सप्लाई लाइन का भी प्रस्ताव रखा गया। जिस सेक्टर-101, 104, 108, 110, 110ए न्यू पालम विहार, पालम विहार, सेक्टर-23, एनएस-48 को पार करते हुए साइबर हब आदि क्षेत्रों में जलापूर्ति होगी। इस लाइन के साथ से नए वर्ष पुराने शहर में जलापूर्ति की मांग को पूरा किया जा सकेगा। बैठक में विहाणा के परिवहन मंडों मूल चंद्र शर्मा, शहरी व्यापारियों में जीएमडीए के लिए जमीन हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की। सेक्टर-107 के एसटीपी के लिए 49.93 एकड़ भूमि नगर लोगों ने अपेक्षित रूप से जारी किया गया। एसटीपी के लिए 40 एकड़ भूमि के लिए नगर नियम मानेसर 3.75 एकड़ भूमि जीएमडीए को हस्तांतरण होगी।



शिविर में जांच करते ग्रामीण।

गुरुग्राम। मानवता स्वास्थ्य शिक्षा फाउंडेशन की ओर से रविवार को सर्वस्वी इंटरनेशनल स्कूल बेगमपुर खेडोला के सहयोग से स्कूल परिसर में निशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच करके उन्हें पारमर्श दिया। आयुर्वाचन, चिरायु व नियोगी कार्ड भी बना गए। आयुर्वाचन, चिरायु व नियोगी कार्ड भी बना गए। आयुर्वाचन थार्मोकॉमोटरों के लिए बैटरी टेस्ट निशुल्क किए गए। मानवता स्वास्थ्य शिक्षा फाउंडेशन के लिए रोगी, पांच रोगी रोलर, संजय कुमार, ललिता वर्मा व कविता सरकार ने कहा कि शिविर सर्जन डा. विरेन्द्र यादव, उप-सिविल सर्जन डा. अनुज गांग के माध्यम से यह शिविर लगाया गया। स्वास्थ्य, शिक्षा फाउंडेशन का मूल उद्देश्य है। स्कूल के चेयरमैन राजपाल सिंह चौहान, उप-चेयरमैन मान सिंह चौहान ने कहा कि भविष्य में भी इस तरह के सामाजिक कार्यों के लिए उनके दरवाजे संरक्षित रहें। इस शिविर में स्कूल की ओर से जगेश कुमार यादव, पीटीएसी टीचर, रविंद्र सिंह, लक्ष्मी बिश्वर सिंह ने विशेष शास्त्रों दिया। इस शिविर में 80 लोगों ने अपेक्षित रूप से जारी किया गया। आयुर्वाचन थार्मोकॉमोटरों के लिए 100 लोग आए, जिनको रुक्त जांच की गई। 30 लोगों को कार्ड बनवाने के लिए जारी किया गया।

कन्या महाविद्यालय में चलाया गया पौद्यारोपण अभियान

गुरुग्राम। सेक्टर-14 स्थित जगजीव कन्या महाविद्यालय में सीईई एवं ईपीएस की ओर से पर्यावरण संस्करण के लिए पौद्यारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जीआईएफएस के एडिशनल चीफ एजिनियरिंग आफिसर सुभाष चंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। सुभाष प्रेया कार्डांग और सीईई साथी ने सुधार अतिथि और महाविद्यालय की ग्रामांशी बैठक में रुद्र राज का स्वापन किया। मुख्य अतिथि ने जीवन में पौदों की आवश्यकता के बारे में विस्तर से बताया। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने के साथ साथ उनका पोषण भी करें। सुभाष प्रेया कार्डांग और सीईई साथी ने अपेक्षित रूप से जारी किया गया। गुरुग्राम के सेक्टर-14 स्थित जगजीव कन्या महाविद्यालय में पौदा लगाने अतिथि। अधिक पौदों की लगाए। गुरुग्राम आफिसर पीटीएसी दिल्ली ने भी अपेक्षित रुद्र राज और आज जीवन में पौदों की आवश्यकता के बारे में बताया। तपत्थान अतिथि, प्राचार्या, संस्था के पदधिकारियों, महाविद्यालय के प्राच्याचार्यों ने मिलकर 50 आयुर्वेदिक पौधे लगाए।

पहलवानों को डा. विजय सिंह नंबरदार ने किया सम्मानित

गुरुग्राम। दोनों में जांच करते ग्रामीणों के बारे में गुरुग्राम के सेक्टर-14 स्थित जगजीव कन्या महाविद्यालय के बारे में सीईई एवं ईपीएस की ओर से पर्यावरण संस्करण के लिए पौद्यारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जीआईएफएस के एडिशनल चीफ एजिनियरिंग आफिसर सुभाष चंद्र यादव, पीटीएसी टीचर, रविंद्र सिंह, लक्ष्मी बिश्वर सिंह ने विशेष शास्त्रों दिया। इस शिविर में 80 लोगों ने अपेक्षित रूप से जारी किया गया। आयुर्वाचन थार्मोकॉमोटरों के लिए 100 लोग आए, जिनको रुक्त जांच की गई। 30 लोगों को कार्ड बनवाने के लिए जारी किया गया।

पहलवानों को डा. विजय सिंह नंबरदार ने किया सम्मानित

गुरुग्राम। दोनों में जांच करते ग्रामीणों के बारे में गुरुग्राम के सेक्टर-14 स्थित जगजीव कन्या महाविद्यालय में पौदा लगाने अतिथि। अधिक पौदों की लगाए। गुरुग्राम आफिसर पीटीएसी दिल्ली ने भी अपेक्षित रुद्र राज और आज जीवन में पौदों की आवश्यकता के बारे में बताया। तपत्थान अतिथि, प्राचार्या, संस्था के पदधिकारियों, महाविद्यालय के प्राच्याचार्यों ने मिलकर 50 आयुर्वेदिक पौधे लगाए।

तीज महोत्सव के दैनंदिन हालांकाने को दर्शाया गया।

गुरुग्राम। दोनों में जांच करते ग्रामीणों के बारे में गुरुग्राम के सेक्टर-14 स्थित जगजीव कन्या महाविद्यालय के बारे में सीईई एवं ईपीएस की ओर से पर्यावरण संस्करण के लिए पौद्यारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जीआईएफएस के एडिशनल चीफ एजिनियरिंग आफिसर सुभाष चंद्र यादव, पीटीएसी टीचर, रविंद्र सिंह, लक्ष्मी बिश्वर सिंह ने विशेष शास्त्रों दिया। इस शिविर में 80 लोगों ने अपेक्षित रूप से जारी किया गया। आयुर्वाचन थार्मोकॉमोटरों के लिए 100 लोग आए, जिनको रुक्त जांच की गई। 30 लोगों को कार्ड बनवाने के लिए जारी किया गया।

तीज महोत्सव के दैनंदिन हालांकाने को दर्शाया गया।

गुरुग्राम। दोनों में जांच करते ग्रामीणों के बारे में गुरुग्राम के सेक्टर-14 स्थित जगजीव कन्या महाविद्यालय के बारे में सीईई एवं ईपीएस की ओर से पर्यावरण संस्करण के लिए पौद्यारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जीआईएफएस के एडिशनल चीफ एजिनियरिंग आफिसर सुभाष चंद्र यादव, पीटीएसी टीचर, रविंद्र सिंह, लक्ष्मी बिश्वर सिंह ने विशेष शास्त्रों दिया। इस शिविर में 80 लोगों ने अपेक्षित रूप से जारी किया गया। आयुर्वाचन थार्मोकॉमोटरों के लिए 100 लोग आए, जिनको रुक्त जांच की गई। 30 लोगों को कार्ड बनवाने के लिए जारी किया गया।

तीज महोत्सव के दैनंदिन हालांकाने को दर्शाया गया।

गुरुग्राम। दोनों में जांच करते ग्रामीणों के बारे में गुरुग्राम के सेक्टर-14 स्थित जगजीव कन्या महाविद्यालय के बारे में सीईई एवं ईपीएस की ओर से पर्यावरण संस्करण के लिए पौद्यारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जीआईएफएस के एडिशनल चीफ एजिनियरिंग आफिसर सुभाष चंद्र यादव, पीटीएसी टीचर, रविंद्र सिंह, लक्ष्मी बिश्वर सिंह ने विशेष शास्त्रों दिया। इस शिविर में 80 लोगों ने अपेक्षित रूप से जारी किया गया। आयुर्वाचन थार्मोकॉमोटरों के लिए 100 लोग आए, जिनको रुक्त जांच की गई। 30 लोगों को कार्ड बनवाने के लिए जारी किया गया।

तीज महोत्सव के दैनंदिन हालांकाने को दर्शाया गया।

गुरुग्राम। दोनों में जांच करते ग

हिमाचल त्रासदी बेलगाम निर्माण

हिमाचल प्रदेश में आई भयानक त्रासदी का कारण नदियों के जलप्रग्रहण क्षेत्र में बेलगाम निर्माण है। बरसात के वर्तमान मौसूल में हिमाचल प्रदेश, पंजाब व हरियाणा भयानक विभिन्निका का सामना कर रहे हैं जिससे इन राज्यों को भारी नुकसान हुआ है। लगातार बरसात ने सूखी नदियों को भयानक रूप दे दिया है जिससे आम जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है, अनेक लोगों की जान गई है तथा संपत्ति के कारण नहीं है, बल्कि यह मरुजूलों की बेलगाम कार्रवाइयों की भी नीति है जिससे प्राप्ति एवं पर्यावरण दायित्व के बीच नाराज़ संलग्न में बाधा पड़ चुकी है। नदियों के जलप्रग्रहण क्षेत्र में होल व रिंजट बाजारों की प्रवृत्ति इस त्रासदी में व्यापक योगदान कर रही है। जलस्रोतों के कालाच बेलगाम मुनाफे की भावना से पैदा हुआ जिससे अक्सर पर्यावरण तथा स्थानीय समुदायों की व्यावहारिक आवश्यकताओं की अनदेखी होती है। नदियों के जलप्रग्रहण क्षेत्र में फैले ये निर्माण यानी पर्यावरण का बाधा डालते हैं।



इतनी खराब स्थिति में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अकेले हिमाचल में 100 से अधिक लोगों की जांच गई है तथा हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट हुई है। बास्तव में यह लालच तथा प्रकृति के बेलगाम दोहन की इच्छा का प्रत्यक्ष नीतीजा है। बिल्डरों, राजनेताओं व नौकरशाहों के 'गठजोड़' ने राज्य को मुश्किल में धकेल दिया है। जब अवैध निर्माण पूरी गति से चलता है तब नौकरशाही अपनी अधिक बंद कर लेती है।

लगातार बरसात ने अचानक बाढ़, भूखलन तथा अन्य आपदाओं को जन्म दिया है जिससे संकट और गहरा गया है। लोगों के जीवन व कृषि पर आने वाला संकट है। इसके साथ ही दोनों राज्यों में भारी आर्थिक त्रुक्सान हुआ है। हरियाणा और पंजाब में सेकड़ों करोड़ के त्रुक्सान का अनुमान है, जबकि हिमाचल प्रदेश में असाधारण रुप से 8,000 करोड़ रुपये की त्रुक्सान का अनुमान है। नदियों के जलप्रग्रहण क्षेत्र में मानव वस्तियों के बेलगाम दोहन एवं कठोर नियम लगाये हैं। दीर्घकालीन रुप से पर्यावरण के टिकाऊपन पर अल्पकालीन आर्थिक ताप की विरोधी देने के नीतीजे कष्टदायक रुप से सामने आ रहे हैं। इस विभिन्निका के सबक हमारे लिए कठोर चेतावनी हैं कि हमारी कार्रवाइयों के पर्यावरण तथा स्थानीय जनता पर गहरे प्रभाव पड़े हैं। ऐसे में आवश्यक है कि न केवल तत्कालीन राहत उपायों के लिए जीवानदेही तय की जाए, बल्कि उस व्यवस्था पर नियामकीय दृष्टिकोण से नजर डाली जाए। जिससे बेलगाम निर्माण की अनुमति दी जाए। यह बाढ़ 'विकास' के प्रति हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तनकारी सिद्ध होनी चाहिए। केवल जिम्मेदार नियोजन तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता से ही हम ऐसी विभिन्निका आवार-बार आने से रोक सकते हैं।

सिविल-सेना संबंधों की पवित्रता

राजनेताओं को सशस्त्र बलों को अकेले छोड़ देना चाहिए। उनका प्रयोग लाभ उठाने के लिए नहीं होना चाहिए। सेनाओं के राजनीतीकरण से बचना होगा।

भूमिंदर सिंह

(लेखक, सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारी हैं)

किसी

राष्ट्रीय पार्टी के आईटी सेल के राष्ट्रीय समव्यक्त द्वारा अपनी विरोधी राजनीतिक पार्टी के सदस्यों व नेताओं के प्रति पूर्णतः पक्षपाती दृष्टिकोण अपनाना अनुचित नहीं कहा जा सकता है। वह अपनी पार्टी के राजनीतिक दृष्टिकोण से सुझावात्मक व उकासावे वाली कार्रवाई कर सकता है और इस विचार से सत्य को थोड़ा 'तोड़-मरोड़' सकता है। लेकिन जब सैन्यधानिक प्रशासन का सवाल हो तो उसके प्रतिवर अनुलंगनीय कार्यों पर सवाल उठाना रचनात्मकता के दायरे से बाहर चला जाता है। इसे किसी कार्रवाई भी अपने घर छोड़ने पड़े हैं। विनाशकारी विभिन्निका आश्चर्यजनक है, घर मलबे में बदल गए हैं और आजीविका नष्ट हो गई है। लेकिन मानवीय त्रुक्सान संपत्ति के त्रुक्सान से आगे जाता है तथा



कौन सी पार्टी उस समय देश की सत्ता में है। लेकिन अक्षम, गलत या पक्षपाती राजनेता कभी कभी इस निष्पक्ष आदर्शों का उल्लंघन या इसकी अनदेखी करते हैं। वे सूलिसिंग की कार्रवाई करने वाले हैं और इस विचार से बाहर कों थोड़ा 'तोड़-मरोड़' सकते हैं। लेकिन जब सैन्यधानिक प्रशासन का सवाल हो तो उसके प्रतिवर अनुलंगनीय कार्यों पर सवाल उठाना रचनात्मकता के दायरे से बाहर चला जाता है। इसे किसी कार्रवाई भी अपने घर छोड़ने पड़े हैं। अब तक यह माना जाता रहा है कि विनाशकारी विभिन्निका के द्वारा आपातकाम सामने आ रहे हैं। लेकिन जब तक यह माना जाता रहा है कि विनाशकारी विभिन्निका के द्वारा आपातकाम सामने आ रहे हैं। भारत के सशस्त्र बलों की क्षमताएं महत्वपूर्ण व उल्लेखनीय हैं वे बाहर चलना रहते हैं। और इस विचार से बाहर कों थोड़ा 'तोड़-मरोड़' सकते हैं। लेकिन जब सैन्यधानिक प्रशासन का सवाल हो तो उसके प्रतिवर अनुलंगनीय कार्यों पर सवाल उठाना रचनात्मकता के दायरे से बाहर चला जाता है। इसे किसी कार्रवाई भी अपने घर छोड़ने पड़े हैं। अब तक यह माना जाता रहा है कि विनाशकारी विभिन्निका के द्वारा आपातकाम सामने आ रहे हैं। लेकिन जब सैन्यधानिक प्रशासन का सवाल हो तो उसके प्रतिवर अनुलंगनीय कार्यों पर सवाल उठाना रचनात्मकता के दायरे से बाहर चला जाता है। इसे किसी कार्रवाई भी अपने घर छोड़ने पड़े हैं। अब तक यह माना जाता रहा है कि विनाशकारी विभिन्निका के द्वारा आपातकाम सामने आ रहे हैं। लेकिन जब सैन्यधानिक प्रशासन का सवाल हो तो उसके प्रतिवर अनुलंगनीय कार्यों पर सवाल उठाना रचनात्मकता के दायरे से बाहर चला जाता है। इसे किसी कार्रवाई भी अपने घर छोड़ने पड़े हैं। अब तक यह माना जाता रहा है कि विनाशकारी विभिन्निका के द्वारा आपातकाम सामने आ रहे हैं। लेकिन जब सैन्यधानिक प्रशासन का सवाल हो तो उसके प्रतिवर अनुलंगनीय कार्यों पर सवाल उठाना रचनात्मकता के दायरे से बाहर चला जाता है। इसे किसी कार्रवाई भी अपने घर छोड़ने पड़े हैं। अब तक यह माना जाता रहा है कि विनाशकारी विभिन्निका के द्वारा आपातकाम सामने आ रहे हैं। लेकिन जब सैन्यधानिक प्रशासन का सवाल हो तो उसके प्रतिवर अनुलंगनीय कार्यों पर सवाल उठाना रचनात्मकता के दायरे से बाहर चला जाता है। इसे किसी कार्रवाई भी अपने घर छोड़ने पड़े हैं। अब तक यह माना जाता रहा है कि विनाशकारी विभिन्निका के द्वारा आपातकाम सामने आ रहे हैं। लेकिन जब सैन्यधानिक प्रशासन का सवाल हो तो उसके प्रतिवर अनुलंगनीय कार्यों पर सवाल उठाना रचनात्मकता के दायरे से बाहर चला जाता है। इसे किसी कार्रवाई भी अपने घर छोड़ने पड़े हैं। अब तक यह माना जाता रहा है कि विनाशकारी विभिन्निका के द्वारा आपातकाम सामने आ रहे हैं। लेकिन जब सैन्यधानिक प्रशासन का सवाल हो तो उसके प्रतिवर अनुलंगनीय कार्यों पर सवाल उठाना रचनात्मकता के दायरे से बाहर चला जाता है। इसे किसी कार्रवाई भी अपने घर छोड़ने पड़े हैं। अब तक यह माना जाता रहा है कि विनाशकारी विभिन्निका के द्वारा आपातकाम सामने आ रहे हैं। लेकिन जब सैन्यधानिक प्रशासन का सवाल हो तो उसके प्रतिवर अनुलंगनीय कार्यों पर सवाल उठाना रचनात्मकता के दायरे से बाहर चला जाता है। इसे किसी कार्रवाई भी अपने घर छोड़ने पड़े हैं। अब तक यह माना जाता रहा है कि विनाशकारी विभिन्निका के द्वारा आपातकाम सामने आ रहे हैं। लेकिन जब सैन्यधानिक प्रशासन का सवाल हो तो उसके प्रतिवर अनुलंगनीय कार्यों पर सवाल उठाना रचनात्मकता के दायरे से बाहर चला जाता है। इसे किसी कार्रवाई भी अपने घर छोड़ने पड़े हैं। अब तक यह माना जाता रहा है कि विनाशकारी विभिन्निका के द्वारा आपातकाम सामने आ रहे हैं। लेकिन जब सैन्यधानिक प्रशासन का सवाल हो तो उसके प्रतिवर अनुलंगनीय कार्यों पर सवाल उठाना रचनात्मकता के दायरे से बाहर चला जाता है। इसे किसी कार्रवाई भी अपने घर छोड़ने पड़े हैं। अब तक यह माना जाता रहा है कि विनाशकारी विभिन्निका के द्वारा आपातकाम सामने आ रहे हैं। लेकिन जब सैन्यधानिक प्रशासन का सवाल हो तो उसके प्रतिवर अनुलंगनीय कार्यों पर सवाल उठाना रचनात्मकता के दायरे से बाहर चला जाता है। इसे किसी कार्रवाई भी अपने घर छोड़ने पड़े हैं। अब तक यह माना जाता रहा है कि विनाशकारी विभिन्निका के द्वारा आपातकाम सामने आ रहे हैं। लेकिन जब सैन्यधानिक प्रशासन का सवाल हो तो उसके प्रतिवर अनुलंगनीय कार्यों पर सवाल उठाना रचनात्मकता के दायरे से बाहर चला जाता है। इसे किसी कार्रवाई भी अपने घर छोड़ने पड़े हैं। अब तक यह माना जाता रहा है कि विनाशकारी विभिन्निका के द्वारा आपातकाम सामने आ रहे हैं। लेकिन जब सैन्यधानिक प्रशासन का सवाल हो तो उसके प्रतिवर अनुलंगनीय कार्यों पर सवाल उठाना रचनात्मकता के दायरे से बाहर चला जाता है। इसे किसी कार्रवाई भी अपने घर छोड़ने पड़े हैं। अब तक यह माना जाता रहा है कि विनाशकारी विभिन्निका के द्वारा आपातकाम सामने आ रहे हैं। लेकिन जब सैन्यधानिक प्रशासन का सवाल हो तो उसके प्रतिवर अनुलंगनीय कार्यों पर सवाल उठाना रचनात्मकता के दायरे से बाहर चला जाता है। इसे किसी कार्रवाई भी अपने घर छोड़ने पड़े हैं। अब तक यह माना जाता रहा है कि विनाशकारी विभिन्निका के द्वारा आपातकाम सामने आ रहे हैं। लेकिन जब सैन्यधानिक प्रशासन का सवाल हो तो उसके प्रतिवर अनुलंगनीय कार्यों पर सवाल उठाना रचनात्मकता के दायरे से बाहर चला जाता है। इसे किसी कार्रवाई भी अपने घर छोड़ने पड़े हैं। अब त

नगर निगमों में पशुओं की अंत्येष्टि के लिए बनेंगे इलेक्ट्रिक शवदाह गृह

- सभी जनपदों में दुर्घट समितियों के गठन को मिलेगा विस्तार, 1.85 लाख से अधिक गोवंश आमजन को सुपुर्द

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में निराप्रित गो आश्रय स्थलों के प्रबन्धन और प्रदेश में दुरध्द उत्पादन, संग्रह की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि किसी भी दशा में मृत पशुओं को नदियों में प्रवाहित न किया जाए। इसके लिए लोगों को व्यवस्था देनी होगी। सभी नगर निगमों में पशुओं, जानवरों की अंत्येष्टि के लिए इलेक्ट्रिक शवदाह गृह का निर्माण कराया जाए। साथ ही चरणबद्ध रूप से इसे अन्य नगरीय निकायों में भी स्थापित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पशु संवर्धन व संरक्षण के लिए सेवाभाव के साथ सतत प्रयासरत है। गोवंश पालकों सहित सभी पशुपालकों के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पात्र लोगों को इसका लाभ मिलना सुनिश्चित कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि निराश्रित गोवंश संरक्षण की दिशा में सतत प्रयासों के संतोषप्रद परिणाम मिल रहे हैं। वर्तमान में 6889 निराश्रित गो आश्रय स्थलों में 11.89 लाख गोवंश संरक्षित हैं। छोटे-छोटे निराश्रित गोवंश स्थलों के स्थान पर बड़े गोवंश स्थल उपर्योगी हो सकते हैं। हमें नस्ल सुधार व गोबरधन प्लाण्ट जैसे कार्यक्रमों को बढ़ाने की जरूरत है। विकास खण्ड तथा जनपद स्तर पर स्थापित वृहद गो आश्रय स्थल इस कार्य के लिए उपर्योगी हो सकते हैं। इन्हें नियोजित रूप से प्रोत्साहित करें। हर विकास खण्ड व जनपद स्तर पर 4000-5000 गोवंश क्षमता के वृहद गो आश्रय स्थल के लिए स्थान चिन्हित किया जाए। प्रत्येक निराश्रित गो आश्रय स्थलों पर केवर टेकर की तैनाती जरूर हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निराश्रित गोवंश संरक्षण का कार्य समाज के सहयोग के बिना कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। निराश्रित गोवंश



**मुख्यमंत्री योगी ने नाग
पंचमी पर प्रदेशवासियों
को दी शुभकामनाएं**

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाग पंचमी के पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय संस्कृति में जीव जन्मु वृश्च वनस्पति सभी के साथ आत्मीय सम्बन्ध जोड़ने की समृद्ध एवं प्राचीन परम्परा है। नाग पंचमी का पर्व प्रकृति के साथ हमारे इस जुड़ाव का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाग पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। हमारे धर्मशास्त्रों में नाग जगृत कुण्डलिनी शक्ति का प्रतीक है। सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु शेषनाग पर ही शयन करते हैं। शेषनाग छत्र बनकर उन्हें छाया प्रदान करते हैं। ज्ञान और मोक्ष के प्रदाता भगवान शिव के आधूषण ही सर्प एवं नाग हैं। सावन में भगवान शिव के पूजन का विशेष महत्व है। श्रावण मास में नाग पंचमी भगवान शिव संग नागों की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शक्ति के प्रतीक नाग पंचमी के पर्व पर हमारे समाज में पारम्परिक रूप से कुश्ती आदि खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें जनता उत्साह के साथ प्रतिभाग करती है।

स्वयं सहायता समूहों के पन्द्रह लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को मिले 1001 करोड़ रुपए

लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मोर्य की स्वीकृति से प्रदेश के 1.4 लाख स्वयं सहायता समूहों के 15 लाख से अधिक परिवारों को 1001.32 करोड़ रुपये की धनराशि निर्गत की गयी है। संगठन एवं 2889 संकुल स्तरीय संघ के माध्यम से विकास कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता, स्वरोजगार, उद्यमशीलता एवं कौशल विकास द्वारा आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य हेतु वृहद् जागरूकता अभियान संचालित किया गया।

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक सी इंदुमती के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

यह धनराश अतगत रिवॉल्विंग फण्ड के रूप में 57150 स्वयं सहायता समूहों को 85.73 करोड़ रुपये तथा 83236 स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि के रूप 915.6 करोड़ की धनराश निर्गत किया गया। दीन दयाल अन्त्योदय योजना., राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लक्ष्यों के दृष्टिगत राष्ट्रवाद, सुशासन और समग्र विकास से अन्त्योदय के लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कृश्ण मार्ग दर्शन में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के 826 विकास खंडों में इंटेंसिव रूप 1008 करोड़ अधिक ग्रामीण परिवारों को 8423 लाख स्वयं सहायता समूहों 55ए763 ग्राम किया जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अभी तक 594456 समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड के रूप में 891.68 करोड़ रुपए एवं 410610 समूहों को सामुदायिक निवेश निधि के रूप में 4516.71 करोड़ रुपए तथा 375790 समूहों को बैंक क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से 3339.56 करोड़ रुपये का ऋण रोजगार सृजन हेतु निर्गत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान डिजिटल क्रांति के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने की दिशा में आजीविका गतिविधियों के सुचारू ढंग से संचालन एवं प्रदेश सरकार के दिशा निर्दशा के अनुसार सितम्बर 2023 तक प्रदेश में 1.18 करोड़ परिवारों को समूह से आच्छादित करने की प्रक्रिया तीव्र गति से अग्रसर है। मिशन स्तर से रणनीति बनाकर समूह से आच्छादित सभी परिवारों को रिवॉल्विंग फण्ड एवं सामुदायिक निवेश निधि से प्रदान कर कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में आजीविका संबंधन करते हुए आत्म निर्भर बनाने की कार्यवाही की जा रही है उप मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन एवं निरंतर दिशा निर्देश में आजीविका मिशन प्रधानमंत्री जी के विजन अनुसार मिशन समूहों की दीदियों के सामाजिक, शैक्षक एवं आर्थिक उत्तयन व स्वावलंबन की दिशा में लगातार अग्रसर है।

**उपचुनाव प्रचार के दौरान
भाजपा प्रत्याशी दाया सिंह
चौहान पर स्थाही फेंकी गई**

मऊ, लखनऊ। घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार करने आए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार दाग सिंह चौहान पर रविवार को स्थाही फेंकी गई। अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्री ने बताया कि चौहान कोपार्गंज ब्लाक में स्थित एक कॉलेज में जन चौपाल समाप्त होने के बाद दूसरे कार्यक्रम में जा रहे थे। उन्होंने बताया कि चौहान अदरी चट्टी पर पहुंचे और वहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं को देखकर अपनी कार से बाहर निकले, उसी दौरान मोनू यादव नामक युवक ने उनके ऊपर काली स्थाही फेंकी दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अत्री ने बताया कि एकाएक हुई इस घटना से अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। इसी बीच, स्थाही फेंकने वाला मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश की जा रही है। घटना के बाद चौहान बिना प्रचार किए ही वापस लौट गए। भाजपा प्रत्याशी चौहान ने इस घटना को अपने खिलाफ विपक्ष की साजिश बताया है। उन्होंने दावा किया कि उपचुनाव में उन्हें मिल रहे व्यापक जनसमर्थन से घबराकर विपक्ष ने ऐसा किया है। दाग सिंह चौहान 2022 में घोसी सीट से ही समाजवादी पार्टी (सपा) के टिकट पर चुने गए थे मगर पिछले महीने वह विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए। घोसी सीट पर उपचुनाव के त्यागपत्र की वजह से रिक्त हुई है। इस सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान पांच सिंतंबर को होगा और बोर्ड की गिनती आठ सितंबर को की जाएगी।

सपा मुखिया अधिकारी से मिले सुपरस्टार एजनीकांत



इसनाम प्राप्ति मा भा उनका बहुत लाकाप्रयता ह। लखनऊ मैं इन दिनों उनका फिल्म जेलर प्रदर्शित हो रही है।

रजनीकांत ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा-अर्घना की अयोध्या, लखनऊ | जाने-माने अभिनेता रजनीकांत ने रविवार को अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा-अर्घना की। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने बताया कि फिल्म अभिनेता ने मंदिर में लगभग 10 मिनट बिताए। राजू दास ने कहा कि मैं रजनीकांत को धन्यवाद देता हूं कि अब तक लोग अयोध्या आने से घबराते थे लेकिन आज देश के अलग-अलग हिस्सों से, अलग-अलग पेशे से और बॉलीवुड से लोग अयोध्या और उप्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं।



सपा सैनिक प्रकोष्ठ की पद्देश कार्यकारिणी घोषित

लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के अनुमोदन से समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल शरद सरन ने प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी है। कर्नल शरद सरन ने प्रदेश कार्यकारिणी में एक प्रदेश उपाध्यक्ष एक प्रदेश महासचिव और एक कोषाध्यक्ष, 14 प्रदेश सचिव, 28 प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और एक विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया है। प्रदेश कार्यकारिणी में कानपुर के राजेन्द्र कुमार को उपाध्यक्ष, गोरखपुर के प्रदीप कुमार को महासचिव और अम्बेडकरनगर के छोटे लाल को कोषाध्यक्ष बनाया गया है।

कार्यों में शिथिलता बरते वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाईः डॉ. संजय निषाद

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मत्स्य मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने निर्देश दिए कि निर्देशालय शासन से निर्गत पत्रों पर समयबद्ध रूप से कार्यवाही सभी अधिकारी सुनिश्चित करें इसमें शिथिलता बरती जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। मछुआ दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत पात्र व्यक्तियों का बीमा कराये जाने हेतु कैम्पों का आयोजन किया जाये। निर्देशालय स्तर से मत्स्य पालकों को तात्कालिक जानकारी, सुविधा के दृष्टिगत हेल्पलाईन नम्बर जारी किया जाये। मंत्री डॉ. संजय निषाद ने यह निर्देश रविवार को मत्स्य विभाग की संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा मत्स्य निर्देशालय के बीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान दिए। समीक्षा बैठक में एनएस रहमानी संयुक्त निदेशक मत्स्य, पुनोति कुमार उप निदेशक मत्स्य, अंजना वर्मा उप निदेशक मत्स्य, डॉ. हरेन्द्र प्रसाद, उप निदेशक मत्स्य, लखनऊ एजाज अहमद नकवी, मुख्य महाप्रबन्धक, मत्स्य विकास निगम लि., लखनऊ उपस्थित रहे। मंत्री संजय कुमार निषष्ठ द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की विस्तृत समीक्षा करते हुए निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत एसएनए खाते में अवमुक्त धनराशि का शतप्रतिशत व्यय अविलम्ब सुनिश्चित किया जाए एवं जो चयनित लाभार्थी परियोजना का कार्य नहीं करा रहे हैं, उन्हें डीएलसी के माध्यम से तत्काल बैक आउट कराते हुए अन्य लाभार्थियों से नियमानुसार कार्य कराया जाय। योजनान्तर्गत कम व्यय करने वाले जनपद कौशाम्बी, वाराणसी, बागपत, रामपुर, सिद्धार्थनगर, लखनऊ, मथुरा, औरैया, महोबा, देवरिया, महराजगंज, अयोध्या, अमेठी के अधिकारियों को तत्काल परियोजनाओं को पूर्ण कराते हुए शत प्रतिशत व्यय किये जाने के बांडे निर्देश दिये गये। बैठक में मत्स्य उत्पादन के त्रुटिपूर्ण आंकड़े अंकित करने वाले जनपदों को भी फिरोजाबाद, बरेली, श्रावस्ती, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, मैनपुरी, कासगंज, लखीमपुरखीरी, प्रयागराज के मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियों को मत्स्य उत्पादन के आंकड़े परीक्षण कर सही-सही रिपोर्ट करने के निर्देश दिये गये तथा समस्त अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि मत्स्य उत्पादन के

वित्तीय संस्थाओं की स्वीकृत परियोजना

लखनऊ। विधानसभा के मॉनसून सत्र में नेता विरोधी दल अग्निलेश यादव ने बन ट्रिलियन इकाईंमी के संकल्प का मजाक उड़ाते हुए सरकार से इसके रोडमैप पर सवाल किया था। तब सीएम योगी ने खड़े होकर विपक्ष के एक-एक सवाल का चुन चुनकर जवाब दिया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अगस्त 2023 का बुलेटिन न सिर्फ सीएम योगी के तर्कों की तसदीक करता है बल्कि आलोचकों को करारा जवाब भी देता है। बुलेटिन में दिए गए आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में जुटे मुख्यमंत्री योगी के सुशासन पर न सिर्फ देश और दुनिया भर के निवेशकों को बुलाटन के अनुसार उत्तर प्रदेश बका व वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत हिस्सेदारी में एक बार फिर सभी राज्यों से आगे रहा है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत हिस्सेदारी में उत्तर प्रदेश 2022-23 में 16.2 प्रतिशत शेयर के साथ लगातार दूसरे वर्ष नंबर बन पर रहा है। 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी ने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, इफांस्ट्रक्चर, कर्नेक्टिविटी के साथ ही उद्योगों की स्थापना के लिए जो इकाईंमिक रिमॉर्स का दौर शुरू किया है वो आरबीआई की ताजा रिपोर्ट में साफ परिलक्षित हो रहा है। 2013-14 से 2020-21 की अवधि में हिस्सेदारी 2021-22 संस्थाओं द्वारा बका की कुल लागत 12.08 प्रतिशत राज्यों की तुलना और तब भी उनमें नंबर बन 2021-22 से महज एक वर्ष 3.4 प्रतिशत मिली है। 2017 के बाद इन 2 परियोजनाओं वह हिस्सेदारी में 1 हो चुकी है। सुशासन और प्रति उनकी दूर है। बैंकों/वित्ती किए गए परि



स्रोतवार आंकड़ों को एकत्रित करते हुए पंजिकाबद्ध किया जाए एवं ट्रैमासिक आधार पर सभी मण्डलीय अधिकारियों द्वारा एवं प्रदेश स्तर से इसका रिव्यु किया जाए।
प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना एवं मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत

2

A photograph showing a group of people seated around a conference table in a formal setting. A man in a pink shirt is gesturing while speaking, and another man in a blue shirt is listening attentively. The background features a large emblem of the state of Jharkhand.

एक्सपटर्स धारित इस रेने पर एक और वो ये ब वित्तीय परियोजनाओं सेदारी में रहा है। के मध्य द 2021- होती हुई द्विंदि 16.2 यानी उपर में परियोजनाओं हयोग प्राप्त कारोबारी सुगमता को बढ़ाने, मौजूदा नियमों का सुचारा क्रियान्वयन करने के जो प्रयास किए हैं उससे प्रदेश में औद्योगिक परियोजनाओं को शुरू करने के लिए एक माहौल बना है। इसी वर्ष फरवरी माह में संपन्न हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव इन्हीं प्रयासों का नतीजा है। बड़ी संख्या में निवेशक अपनी परियोजनाओं को उपर में स्थापित करने के लिए लालायित हैं। इन उद्यमों की आर्थिक आवश्यकताओं को देखते हुए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का भी उत्साह बढ़ा है और

हानी प्रति रुपए में यह अन्य राज्यों में तो दर्ज की गई है। अन्य राज्यों में हिस्सेदारी का प्रतिशत 2013-14 से 2020-21 के बीच औसतन 9.4 से लुढ़ककर 2021-22 में 4 और 2022-23 में 5.5 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

योगी सरकार ने विंगत 6 वर्षों में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुशासन को बेहतर करने, कारोबारी निर्णय में तेजी लाने एवं राजनीति पर उत्तराधिकारी की विभागीय विभागों को विभागीय विभागों के लिए स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त इन निवेश प्रस्तावों के ध्यानात्मक पर उत्तरने के साथ ही यह हिस्सेदारी और भी नए प्रतिमान स्थापित करेगी और सीएम योगी के बन ट्रिलियन डॉलर इकानमी के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी।

